607वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 नवम्बर 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 607वीं बैठक दिनांक 21/11/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No 9082/2022 Shri Jagdish S/o Shri Ramchandra, Village - Jabardi, Tehsil - Pachore, Dist. Rajgarh, MP Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 2.0 ha. (20000 cum per annum) (Khasra No 507/2), Village - Jamonya Johar, Tehsil - Narsinghgarh, Dist. Rajgarh (MP) EIA Consultant: Green Circle Vadodara (Guj.)</u>

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No 507/2), Village - Jamonya Johar, Tehsil - Narsinghgarh, Dist. Rajgarh (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 562वीं दिनांक 29/03/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 21/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री जगदीश विश्वकर्मा और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में 155 एवं पूर्व दिशा में 412 मीटर पर पक्का रोड़ है तथा पश्चिम दिशा में 435 मीटर पर कुछ मकान है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण मुरूम की माईनिंग का है जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है अतः रोड़ एवं मकान एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 21/07/20 में निर्धारित 100 मीटर की दूरी से अधिक है । इसी प्रकार खदान के दक्षिण–पश्चिम दिशा

में 850 मीटर पर तालाब के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इसके सरंक्षण हेतु गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक प्रस्तावित किये गये है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान के पूर्वी भाग के समीप से कच्चा रोड़ निकल रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह कच्चा रोड़ उनके व आसपास के क्षेत्र में कार्यरत अन्य खदानों का पहुंच मार्ग है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा स्कूल में पुताई, सडको पर पानी का छिडकाव तथा वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके चेप्टर क्रमांक 13 के सरल क्रमांक 21 (पेज क्रमांक 49) पर इस खदान का विवरण दर्ज है।

प्रकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 284 दिनांक 08/03/22 अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र नरसिंहगढ़ वन्य प्राणी अभ्यारण्य से 1.16 किलोमीटर की दूरी पर होना उल्लेखित है जबकि संबंधित नोटिफिकेशन दिनांक 27/07/18 में पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (ई.एस.जेड.) की सीमा 100 मीटर से 02 किलोमीटर तक दूरी तक निर्धारित है, अतः एकल प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं होता है कि आंवटित खनन् क्षेत्र पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा के अंदर है अथवा नहीं । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वन मण्डाधिकारी, राजगढ़ ने पत्र क्रमांक 20 दिनांक 05/01/22 के माध्यम से यह सूचित किया है कि आवेदित स्थल खसरा क्रमांक 507/2 नरसिंहगढ़ के अधिसूचित परिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा से 161 मीटर की दूरी पर स्थित है । समिति ने परिवेश पोर्टल पर इस खदान की स्थिति समझने हेतु जब ईको–सेंसेटिव जोन की लेयर अपलोड की तो आवेदित स्थल परिवेश पोर्टल अनुसार अधिसूचित परिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा के अंदर दिख रहा है ।

समिति ने पाया कि एक अन्य प्रकरण क्रमांक 8934/2022 जो इसी खसरे आवंटित एक अन्य खदान है, में सेक की 604वीं बैठक दिनांक 05/11/22 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था :–

''प्रकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र दिनांक 16/09/21 अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र नरसिंहगढ़ वन्य प्राणी अभ्यारण्य से 1.480 किलोमीटर की दूरी पर होना उल्लेखित है जबकि संबंधित नोटिफिकेशन दिनांक 27/07/18 में पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (ई.एस.जेड.) की सीमा 100 मीटर से 02 किलोमीटर तक दूरी तक निर्धारित है, अतः एकल प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं होता है कि आंवटित खनन् क्षेत्र पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा के अंदर है अथवा नहीं । अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि संबंधित वन मण्डलाधिकारी से यह स्पष्ट प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये कि आवंटित खनन् क्षेत्र नरसिंहगढ़ वन्य प्राणी अभ्यारण्य की अधिसूचित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (ई.एस.जेड.) की सीमा से बाहर कितनी दूरी पर स्थित है। समिति की यह भी अनुशांसा है कि सिया द्वारा जो एकल–प्रमाणपत्र का प्रारूप दिया गया है उसमें डी.एफ.ओ. से यह स्पष्ट उल्लेख करवाया जाये कि प्रस्तावित खदान वन क्षेत्र से कितनी दूरी पर स्थित है एवं यदि खदान अधिसूचित ई.एस.जेड. के पास स्थित है तो वह ई.एस.जेड. से कितनी दूरी पर है तथा अधिसूचित ई.एस.जेड की सीमा से बाहर है ताकि प्रकरणो के निराकरण में सुविधा हो''।

उपरोक्त संदर्भ में सिया ने पत्र क्रमांक 2039 दिनांक 11/11/22 के माध्यम से सूचित किया है कि प्रकरण क्रमांक 8934/2022 के संदर्भ में वन मण्डलाधिकारी, कार्यालय वन मण्डल, सामान्य, राजगढ़ (व्यावरा) म.प्र. ने पत्र क्रमांक 2758 दिनांक 06/11/22 के माध्यम से सूचित किया है कि मान्नीय

सर्वोच्च न्यायालय के रिट पिटिशन (एस) (सिविल) 202/1995 में पारित आदेश दिनांक 03/06/2022 के बिंदु क्रमांक–44(बी) अनुसार सर्वे क्रमांक 507/2 रकबा 18.564 हे. में से अंश रकबा 01.00 हे. पर नवीन मुरम उत्खनन् पट्टा जामोन्या जोहर तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ वन्यप्राणी अभ्यारण्य नरसिंहगढ़ की अधिसूचित परिस्थितिकीय संवेदी जो (ईको सेंसेटिव जोन) की सीमा 02 किलोमीटर के अंदर 1630 मीटर पर स्थित है । मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के आधार पर अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में कोई स्वीकृति जारी नहीं की जायें ।

अतः समिति ने उपरोक्त परिप्रेक्ष्य चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि चूँकि दोनों खदानें (प्रकरण क्रमांक–8934/2022 एवं 9082/2022) एक ही खसरे 507/2 पर आवंटित है, अतः इस प्रकरण में भी संबंधित वन मण्डलाधिकारी से यह स्पष्ट प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये कि आवंटित खनन् क्षेत्र नरसिंहगढ़ वन्य प्राणी अभ्यारण्य की अधिसूचित परिस्थितिकीय संवेदी जोन (ई.एस.जेड.) की सीमा से बाहर है तथा उनको इस आवेदित स्थल पर खनन् करने से विभाग कोई आपत्ति नहीं है ।

2. <u>Case No. - 5697/2018 Dy. Inspector General of Police (Works), Group Center, Centre Reserve Police Force (CRPF), Gwalior,(M.P.) – 474003. Prior Environment Clearance for Proposed Residential Colony in Existing CRPF Campus Area as C/o 1003 Nos. Staff Quarters (900 Nos. Type II, 54 Nos. Type III, 33 Nos. Type IV, 16 Nos. Type V quarters) at Khasra No. – 560/1, 543, 561/1 (1/4) (K1/2) Village - Nayagaon, Tehsil – Gwalior, Distt.- Gwalior, (M.P.). Total Plot Area – 2,07,860.00 m2, Total Construction Area – 72,946.48 m2. Cat. - 8(a) Building and Construction Projects. For Building Constuction. Env. Con. – Mantras Green Resources Ltd. Kalyan (Maharastra).</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Residential Colony in Existing CRPF Campus Area as C/o 1003 Nos. Staff Quarters (900 Nos. Type II, 54 Nos. Type III, 33 Nos. Type IV, 16 Nos. Type V quarters) at Khasra No. – 560/1, 543, 561/1 (1/4) (K1/2) Village - Nayagaon, Tehsil – Gwalior, Distt.- Gwalior, (M.P.). Total Plot Area – 2, 07,860.00 m^2, Total Construction Area – 72,946.48 m2. Cat. 8(a) Building and Construction Projects.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 328th SEAC dated 08/09/2018 wherein ToR was recommended and isued vide letter NO. 315/PS-MS/MPPCB/SEAC/TOR(328)/2018 dated 22/09/18 as follows:

This case was scheduled in this meeting wherein PP and their consultant were present. During discussion and perusals of the documents it was observed by the committee that the It's a case of Violation. After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC Notification dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in this notification and the project may granted Terms of Reference

for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

PP during presentation stated that they have already carried-out the monitoring from Nov-Jan and requested to use that monitoring data, committee allow to use that data along with one month validation data. Hence committee recommended to issue additional TOR as per notification dated 08th March 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA as follows:-

1. *Project description, its importance and the benefits.*
2. *Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, Google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.*
3. *Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.*
4. *Land acquisition status, R & R details.*
5. *Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.*
6. *Baseline environmental study for ambient air (PM10, PM2.5, SO_2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one month (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.*
7. *Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area*
8. *Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.)*
9. *Source of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.*
10. *Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project*

and also the study area

11. *Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.*
12. *Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.*
13. *Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.*
14. *Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.*
15. *The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.*

PP vide proposal no. SIA/MP/MIOS/240343/2021has applied for extention of TOR validity which was considered by SEIAA and TOR validity was extended for one more year. PP has submitted the EIA report (online on dated 14/07/22) which subsequently forwarded by SEIAA to SEAC (on-line received on 09/11/22) and the same was scheduled in the agenda.

The case was presented by PP Mr. Omkar Nath Singh, Commendant, CRPF and Shri Arun Tiwari, AE, CPWD, Gwalior and their environmental consultant Ms. Abha Garg, M/s. Mantras Green Resources Lts., Kalyan, Maharashtra. During presentation PP submitted that it's a case of violation where construction was begin without prior EC.

Salient Features of the Project

1. Name of The Project: CRPF 1003 Nos. staff Quarters (900 Nos. TypeII, 54 Nos. Type-III, 33 Nos. Type- IV, 16 Nos. Type –V quarters) for Group Centre, CRPF at Gwalior, Madhya Pradesh.

2	Category as per EIA Notification Schedule	:	8(a) -Voilation
3	Land	:	Already acquired
4	Topography	:	Open Barren Land
5	Plot Area:	:	2,07,860 Sq. mt

6	Total Builtup area	:	72,946.48 Sq. mt
7	Ground coverage area	:	24,216 Sq.mt
8	RG area	:	1,83,644 Sq. mt
9	Top Terrace Area	:	24,408 Sq. mt
10	Water Supply	:	Borewell
11	Power Supply	:	MPPKVVCL
12	Railway Station	:	Panihar at 2.8 km (W)
13	Road	:	AH 47 0.85 km (East)
14	Nearest Town	:	Gwalior 9.80 Km (NE)
15	Nearest Reserve Forest /Protected Forest	:	Ghatigaon Sanctuary 4.5 km.
16	Nearest Water Bodies	:	Tighara Dam 9.77km NW

During presentation it was submitted by the PP it's a case of voilation because the construction was done without prior EC and thus they have filled the application under violation category and obtained TOR to carryout EIA.

During presentation committee members raise following issues which needs to be addressed before appraisal:

1. The contents of EIA report uploaded by the PP/Consultant are not legible and many figures (such as 2.6, 2.7, 2.13, 2.15 &3.17) and tables (such as 3.6,3.8,3.9 etc) are bulrred and thus can not be understood and analysed.
2. Project area with all co-ordinates are not marked and uploaded on Parivesh portal. Only one co-ordiante is provided and thus it is difficult to locate the entire project area.
3. Pointwise compliance report of TOR is not provided which shall be a part of the EIA report.
4. Damage assessment shall be quantified wrt volume and amount with backup calculation.
5. As per the Google image of 2015-16, it appears that entire area is lush green and occupied by trees. However, during deliberations PP stated that these are herbs and bushes, thus PP shall submit documentary evidences in support of their statement and if trees/bushes are uprooted, shall be part of damage assessment.

The committee after deliberated recommends that PP shall re-submitted EIA report as discussed above and containing all data, figures and tables in legible form for further consideration of the case.

3. <u>Case No. - 5698/2018 Dy. Inspector General of Police (Works), Group Center, Centre Reserve Police Force (CRPF), Gwalior, (M.P.) Prior Environment Clearance for Proposed Construction of 5 Nos. 240 Men Barracks including Electrical Works for Group Centre Khasra No. – 560/1, 543, 561/1 (1/4) (K1/2) at Village - Nayagaon, Tehsil – Gwalior, Distt. - Gwalior, (M.P.) Total Plot Area – 14,060 Sq.m RG Area – 6,817 Sq.m., Proposed Ground Coverage Area – 7,243 Sq.m, Total Construction Area – 21,316.15 m2. Cat. - 8(a) Building and Construction Projects. For Building Constuction. Env. Con. – Mantras Green Resources Ltd. Kalyan (Maharastra).</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Construction of 5 Nos. 240 Men Barracks including Electrical Works for Group Centre Khasra No. – 560/1, 543, 561/1 (1/4) (K1/2) at Village - Nayagaon, Tehsil – Gwalior, Distt. - Gwalior, (M.P.) Total Plot Area – 14,060 Sq.m RG Area – 6,817 Sq.m., Proposed Ground Coverage Area – 7,243 Sq.m, Total Construction Area – 21,316.15 m^2.Cat. 8(a) Building and Construction Projects.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 328th SEAC dated 08/09/2018 wherein ToR was recommended and isued vide letter NO. 317/PS-MS/MPPCB/SEAC/TOR(328)/2018 dated 22/09/18 as follows:

This case was scheduled in this meeting wherein PP and their consultant were present. During discussion and perusals of the documents it was observed by the committee that the It's a case of Violation. After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC Notification dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in this notification and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

PP during presentation stated that they have already carried-out the monitoring from Nov-Jan and requested to use that monitoring data, committee allow to use that data along with one month validation data. Hence committee recommended to issue additional TOR as per notification dated 08th March 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA as follows:-

1. *Project description, its importance and the benefits.*
2. *Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, Google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.*
3. *Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.*
4. *Land acquisition status, R & R details.*
5. *Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.*
6. *Baseline environmental study for ambient air (PM10, PM2.5, SO_2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one month (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.*
7. *Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area*
8. *Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.)*
9. *Source of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.*
10. *Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area*
11. *Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.*
12. *Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.*
13. *Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.*
14. *Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community*

resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.

15. *The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.*

PP vide proposal no. SlA/MP/MlS/240328/2021 has applied for extension of TOR validity which was considered by SEIAA and TOR validity was extended for one more year. PP has submitted the EIA report (online on dated 14/07/22) which subsequently forwarded by SEIAA to SEAC (on-line received on 09/11/22) and the same was scheduled in the agenda.

The case was presented by PP Mr. Omkar Nath Singh, Commendant, CRPF and Shri Arun Tiwari, AE, CPWD, Gwalior and their environmental consultant Ms. Abha Garg, M/s. Mantras Green Resources Lts., Kalyan, Maharashtra. During presentation PP submitted that it's a case of violation where construction was begin without prior EC.

Salient Features of the Project

Sr. No.	Particulars	Details
1	Name of The Project	The project Barracks including Electrical Works for Group Centre at CRPF Gwalior at Village Panihar, Dist. Gwalior, Madhya Pradesh
2	Category as per EIA Notification	Schedule 8(a)
3	Land	Already acquired
4	Topography	Open Barren Land
5	Plot Area	14,060 Sq.m
6	Total Builtup area	21,316.15 Sq. m
7	Ground coverage area	7,243 Sq.m
8	RG area	6,817 Sq. m
9	Top Terrace Area	7,243 Sq. mt
10	Water Supply	Borewell
11	Power Supply	MPPKVVCL, Madhya Pradesh Paschim KshetraVidyut Vitran Company Ltd. Indore (MP)
12	Railway Station	Panihar Railway station at 2.8 km distance(West)

13	Road	AH47 (Mumbai – Agra Highway) – 0.85 km(East)
14	Nearest Town	Gwalior at 9.80 Km North-East
15	Nearest Reserve Forest /Protected Forest	Ghatigaon Sanctuary is at a distance of 4.5 kmfrom the project site.
16	Nearest Water Bodies	Tighara Reservoir which is 9.77 km awaytowards NW direction from proposed project

During presentation it was submitted by the PP it's a case of voilation because the construction was done without prior EC and thus they have filled the application under violation category and obtained TOR to carryout EIA.

During presentation committee members raise following issues which needs to be addressed before appraisal:

1. The contents of EIA report uploaded by the PP/Consultant are not legible and many figures (such as 2.4, 3.3, 3.4 , 3.6, 3.8 , 3.9, 3.10, 3.11, 3.13 3.14, 3.18, 4.1 etc.) and tables (such as 1.4, 2.9, 3.1, 3.6, 3.8 etc) and water balance chart on page no. 22, are blurred and thus cannot be understood and analyzed.
2. Project area with all co-ordinates are not marked and uploaded on Parivesh portal. Only one co-ordiante is provided and thus it is difficult to locate the entire project area.
3. Pointwise compliance report of TOR is not provided which shall be a part of the EIA report.
4. Damage assessment shall be quantified wrt volume and amount with backup calculation.
5. As per the Google image of 2015-16, it appears that entire area is lush green and occupied by trees. However, during deliberations PP stated that these are herbs and bushes, thus PP shall submit documentary evidences in support of their statement and if trees/bushes are uprooted, shall be part of damage assessment.

The committee after deliberated recommends that PP shall re-submitted EIA report as discussed above and containing all data, figures and tables in legible form for further consideration of the case.

4. <u>Case No 9411/2022 M/s Basa Buildcon Partner- Shri Abul Vakar, R/o- G-9, Jhumera Complex Near Hotel Manal, A.B. Road Vishwas Banjari, Post - Bhatkhedi, Tehsil - Mhow, District Indore (M.P.), Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.0 ha. (50000 Cum per annum) (Khasra No. 1021/1, 753), Village - Kheda, Tehsil - Dhar, Dist. Dhar (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1021/1, 753), Village - Kheda, Tehsil - Dhar, Dist. Dhar (MP) 3.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अबुल बाकर (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1328 दिनांक 30/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 11 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर दिशा में 240 मीटर पर, उत्तर–पश्चिम दिशा में 490 मीटर पर, पूर्व दिशा में 690 मीटर पर आबादी तथा दक्षिण दिशा में 690 मीटर पर व्हीकल टेस्टिंग ट्रेक है अतः इनकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे। प्रश्नाधीन खदान में 02–03 क्रेशर स्थापित है अतः इनके विवरण व क्या इनका उपयोग इस खदान हेतु किया जायेगा का विवरण मय फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। समिति ने पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान का विवरण दर्ज नही है अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करें । इसी प्रकार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम सभा की एन.ओ.सी ऑन लाईन अपलोड नही की गई है अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ ग्राम सभा की एन.ओ.सी प्रस्तुत करे । **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र में पूर्व से पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।** उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के उत्तर दिशा में 240 मीटर पर, उत्तर–पश्चिम दिशा में 490 मीटर पर, पूर्व दिशा में 690 मीटर पर आबादी तथा दक्षिण दिशा में 690 मीटर पर व्हीकल टेस्टिंग ट्रेक है अतः इनकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।

2. प्रश्नाधीन खदान में 02–03 क्रेशर स्थापित है अतः इनके विवरण व क्या इनका उपयोग इस खदान हेतु किया जायेगा का विवरण मय फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ वन विभाग से चर्चा कर यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
6. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. के साथ डी.एस.आर. जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करे ।

5. <u>Case No 9399/2022 M/s Rewa Minerals and Company, Partner, Shri Akhand Pratap Singh, Ward No. 26, Near CDI Bunglaw, Pandaw Nagar, Saman, Tehsil - Huzur, DIst. Rewa, MP - 486001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (18,468 Cum per annum) (Khasra No. 8/2/1/2), Village - Harrahaa, Tehsil - Mauganj, Dist. Rewa (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 8/2/1/2), Village - Harrahaa, Tehsil - Mauganj, Dist. Rewa (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अंखड प्रताप सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इनवॉयरोटेक इंडिया प्रा. लि. कांसल्टेंट, लखनऊ उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2616 दिनांक 01/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में

06 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर दिशा में 35 मीटर की दूरी पर तथा पश्चिम दिशा में 100 मीटर की दूरी पर प्राकृतिक नाला एवं दक्षिण दिशा में 80 मीटर पर रोड है । इसी प्रकार एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2616 दिनांक 01/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान से शाला भवन एवं पंचायत भवन 300 मीटर, 05–06 मकान 200 मीटर पर स्थित है (गूगल इमेज अनुसार निकटतम् आवास 50 मीटर पर) अतः इनकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियेाजना प्रस्तावक ने बातया कि इस प्रकरण में वे ब्लास्टिंग के स्थान पर रॉक ब्रेकर का उपयोग खनन् हेतु करेंगे । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल रीवा के पत्र क्रमांक 903 दिनांक 31/01/22 अनुसार खदान से वन क्षेत्र की दूरी 70 मीटर पर है जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने संभागीय आयुक्त समिति से बैठक दिनांक 29/12/21 ने अनुमति प्राप्त की है। समिति ने पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान का विवरण दर्ज नही है अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करें । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के उत्तर दिशा में 35 मीटर की दूरी पर तथा पश्चिम दिशा में 100 मीटर की दूरी पर प्राकृतिक नाला एवं दक्षिण दिशा में 80 मीटर पर रोड है । इसी प्रकार एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2616 दिनांक 01/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान से शाला भवन एवं पंचायत भवन 300 मीटर, 05–06 मकान 200 मीटर पर स्थित है अतः इनकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

7. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. के साथ डी.एस.आर. जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करे ।

6. <u>Case No 9404/2022 Shri Sanjay Mastana, Owner, Ward No. 4, Shivaji Nagar, Tehsil - Silwani, Dist. Raisen, MP 464886, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (25,001.625 Ton per annum) (Khasra No. 384), Village - Mahuakheda Khurd, Tehsil - Begumganj, Dist. Raisen (MP)</u>

This is case of for Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 384), Village - Mahuakheda Khurd, Tehsil - Begumganj, Dist. Raisen (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज सेक की 607वीं बैठक दिनांक 21/11/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

7. <u>Case No 9405/2022 Smt. Meera Bodkhe, Owner, H/No. 67/1, Kamath Nagpur Road, Tehsil - Multai, Dist. Betul, MP - 460661 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (5924 Cum per annum) (Khasra No. 153/2), Village - Hardoli, Tehsil - Multai, Dist. Betul (MP)</u>

This is case of for Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 153/2), Village - Hardoli, Tehsil - Multai, Dist. Betul (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री मीरा बोडखे (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1289 दिनांक 01/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान

स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 5.00 हे. से कम होने के कारण प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर दिशा में 250 मीटर की दूरी पर एक ओर खदान स्थित है जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1289 दिनांक 01/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान बहुत पुरानी है तथा गूगल इमेज अनुसार 2008 से इसमें खनन् कार्य चालू हुआ है । **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस खदान में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति में निहित शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस खदादन द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पश्चिम दिशा में 225 मीटर तथा पूर्व दिशा में 110 मीटर पर रोड़ है । इसी प्रकार खदान के पश्चिम दिशा में 30 मीटर पर प्राकृतिक नाला तथा 650 मीटर पर हरडोली बॉध है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्राकृतिक नाले के सरंक्षण हेतु मध्य प्रदेश एम.एम.आर., 1996 के प्रावधान अनुसार 20 मीटर का सेट वेक प्रस्तुतीकरण में दिया गया है तथा नाले व बॉध के सरक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक प्रस्तावित किये गये है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिर्पोट अपलोड की गई थी किन्तु तकनीकी खराबी के कारण ऑन लाईन दिख नही रही है इस खदान का विवरण जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 39 के सरल क्रमांक–5 पर दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 5,924 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.35 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 02.68 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
ग्राम हरदोली में ग्राम पंचायत के परामर्श से हैंडपंप लगवाया जावेगा	60,000/–
योग	60,000/–

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आवला, खमेर, नीम, चिरोल, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू ,पीपल आदि।	350
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, करंज, सप्तपर्णी, चिरोल, बरगद, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, सिस्सू आदि।	200
3	ग्राम हरदोली के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	आवला, कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, आम, कटहल, करंज आदि।	60
4	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	आवला, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, अनार, निम्बू, कटहल आदि।	590
		कुल	**1200**

8. <u>Case No 9406/2022 Shri Pushpraj Singh Tiwari, Owner, Village- Chulhi, Tehsil - Kotar, Dist. Satna, MP - 485005, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.550 ha. (11250 Cum per annum) (Khasra No. 13/3/1), Village - Chulhi, Tehsil - Kotar, Dist. Satna (MP)</u>

This is case of for Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 13/3/1), Village - Chulhi, Tehsil - Kotar, Dist. Satna (MP) 1.550 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री पुष्पराज सिंह तिवारी, (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इनवॉयरोटेक इंडिया प्रा. लि. कांसल्टेंट, लखनऊ उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1296 दिनांक 04/07/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, तथा कुल रकबा 5.00 हे. से कम होने के कारण प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। एकल प्रमाण–पत्र अनुसार खदान वन कक्ष क्रमांक आर.एफ.–781 की वनसीमा से 50 मीटर की दूरी पर है तथा कार्यालय कमिश्नर, रीवा के पत्र क्रमांक 4493 रीवा दिनांक 05/10/18 के अनुसार अनुमति प्राप्त है (संभाग स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 3/10/2018 में अनुमोदित)।

607वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 नवम्बर 2022

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर रोड़ तथा 130 मीटर पर आबादी है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि एन.जी.टी. के दिनांक 21/7/20 के अनुसार 70 मीटर का सेट बेक (नॉन माईनिंग जोन–0.27 हे.) छोडा जायेगा जिस कारण 1.55 हे. क्षेत्र में से खनन् हेतु 1.28 हे. क्षेत्र उपलब्ध होगा। आवटित खनन् क्षेत्र के उत्तरीय दिशा में खदान के समीप एक मकान है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक से बताया कि यह उनका स्वयं का मकान है, जिसका उपयोग कृषि के उपकरण व अनाज इत्यादि रखने हेतु किया जाता है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 1884 दिनांक 02/11/22 के द्वारा सूचित किया है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2022–23 में बनी है, जिमसें ग्राम चुल्ही शामिल है । जिला कार्यालय में भेजे गये डीएसआर में प्रस्ताव में उक्त खनिपट्टा सरल क्रमांक सरल क्रमांक–180 पर शामिल है जो त्रुटि पूवर्क एप्रूव्ड डी.एस.आर. में छूट गया था, जिसे पृथक–पृथक खनिज के लिए भेजे गये डी.एस.आर. में जोड़ लिया जायेगा । इस संबंध में समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 11,250 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.38 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 05.00 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
ग्राम चुल्ही के ऑगनवाड़ी केन्द्र में खाना बनाने के लिये खाना परोसने के लिये और बच्चों के खाना खाने के लिये बर्तन व बच्चों के खेलने के लिए के लिए लकडी के खिलौने तथा बची हुई राशि से 1वर्ष तक पोषण आहार का वितरण किया जाएगा।।	60,000/–
योग	60,000/–

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1680 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**

1	बैरियर जोन मे	शीशम, नीम, बरगद, खमैर, चिरौल, पीपल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	560
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, अमलतास एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ,	300
3	वन सीमा की और से 50 मीटर तक बफर जोन	शीशम, नीम, बरगद, खमैर, चिरौल, पीपल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	1000
		योग	1680

9. <u>Case No 9407/2022 Shri Vijay Raghuwansi, Owner, Kalapatha, Near Chattan, Tehsil & Dist. Betul, MP - 460001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.950 ha. (25,000 Cum per annum) (Khasra No. 112/2), Village - Gehunras, Tehsil - Betul, Dist. Betul (MP)</u>

This is case of for Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 112/2), Village - Gehunras, Tehsil - Betul, Dist. Betul (MP) 1.950 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री विजय रघुवंशी, (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 575 दिनांक 06/04/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है (जिसकी अवधि दिनांक 27/06/20 को समाप्त) इस प्रकार कुल रकबा 5.00 हे. से कम होने के कारण प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस खदान इस खदान के पास में सिथत एक अन्य खदान में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति में निहित शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस खदादन द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्व दिशा में 90 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा पश्चिम दिशा में 125 मीटर पर प्राकृतिक नाला है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इसके संरक्षण हेतु गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टेक प्रस्तावित किये गये है । आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तर दिशा में लगे हुआ 02 शेड है तथा खनन् क्षेत्र के अंदर भी 01 शेड है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् क्षेत्र के अंदर जो शेड दिख रहा है, वह आंवटित खनन् क्षेत्र के दक्षिण दिशा में स्थापित क्रेशर का साइट आफिस है, जो वर्तमान में अनुपयोगी है । इसी प्रकार खनन् क्षेत्र के उत्तरीय दिशा के समीप जो 02 शेड स्थापित हैं, वह हमारे

द्वारा खुद की निजी भूमि पर अभी हॉल ही में निर्मित कराये गये है, जिनका उपयोग इस खनन् कार्य में उपयोग आने वाले उपकरणों के रखने व साइट आफिस के रूप में किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा जारी एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 575 दिनांक 06/04/2022 यह उल्लेखित है कि यह मकान निजी भूमि खेत में निर्मित है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा बैतूल जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके पेज नं. 39 के सरल क्रमांक–4 पर इस खदान का विवरण दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 25,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.22 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 03.51 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
उत्खनिपट्टे में पश्चिम में लगभग 300 मीटर पर स्थित चेक डैम की साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण के साथ साथ उसके आस पास पौधरोपण करवाया जावेगा ।	**60,000/-**
योग	**60,000/-**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2340 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, चिरोल, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल आदि।	800
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, करंज, सप्तपर्णी, चिरोल, बरगद, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, सिस्सू आदि।	300
3	ग्राम गेहूरास के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	मुनगा, कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पपीता, आम, कटहल ,आवला करंज, आदि।	60
4	ग्राम गेहूरास के विद्यालय परिसर में	चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, करंज, नीम, पीपल, कदम आदि।	180

5	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	आवला, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, अनार, निम्बू, कटहल आदि।	1000
		कुल वृक्षारोपण	**2340**

10. <u>Case No 9408/2022 Shri Purvansh Tiwari, Owner, Jawahar Ward, Dist. Betul, MP - 460001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (Stone – 5880 Cum per annum and Murrum - 7500 Cum per annum) (Khasra No. 14/2), Village - Junawani, Tehsil - Betul, Dist. Betul (MP)</u>

This is case of for Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 14/2), Village - Junawani, Tehsil - Betul, Dist. Betul (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री पुर्वांश तिवारी, (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 763 दिनांक 11/05/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में उल्लेखित किया है कि आवेदित क्षेत्र नवीन नहीं है जिसके कुछ भाग पर पूर्व में पत्थर उत्खनिपट्टा स्वीकृत रहा था, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है तथा अन्य किसी खदान की जानकारी नहीं दी गई है, इस आधार प्रकरण बी–2 श्रेणी के माना जा सकता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण–पूर्व दिशा में 170 मीटर पर आबादी तथा 210 मीटर पर रोड हैं । आबादी के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा 30 मीटर का सेटबैक (नॉन माइनिंग जोन) प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है । इसी प्रकार आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तरी–पूर्वी दिशा में कुछ पेड़ लगे हैं जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पेड़ पूर्व में कार्यरत खदान द्वारा लगाये गये थे, जिनको नहीं काटा जायेगा तथा जिस क्षेत्र में यह पेड़ लगे हैं, उनको भी नॉन माईनिंग जोन प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है । आवंटित खनन् क्षेत्र में एक पुराना पिट है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको यह खदान इसी स्थिति में आवंटित हुई है, जिसका विवरण अनुमोदित खनन् योजना में दिखाया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा बैतूल जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके पेज नं. 39 के सरल क्रमांक–3 पर इस खदान का विवरण दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 5,880 मी^{3} प्रति वर्ष एवं मुरूम – 7,500 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.83 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 02.68 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
जुनावानी ग्राम के बाल शिक्षा केंद्र की मर्रमत एवं पुताई करवाई जावेगी साथ ही उक्त केंद्र में जरूरत के हिसाब से सामग्री उपलब्ध करवाई जावेगी	**60,000/-**
योग	**60,000/-**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, आवला, खमेर, चिरोल, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल आदि।	400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, करंज, सप्तपर्णी, चिरोल, बरगद, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, सिस्सू आदि।	200
3	खदान में प्रस्तावित गैर खनन क्षेत्र में	नीम, आवला , खमेर, चिरोल, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल आदि।	100
4	ग्राम जूनावानी के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	नीम, कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पपीता, आम, कटहल, आवला करंज, आदि।	50
5	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	आवला, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, अनार, इमली, निम्बू, कटहल आदि।	450
		कुल	**1200**

11. <u>Case No 9409/2022 Shri Sana Ul Haq, Owner, Talab Road, Forest Dipo, Dist. Raisen, MP - 464551 Prior Environment Clearance for Flag Stone Quarry in an area of 1.314 ha. (2400 Cum per annum) (Khasra No. 209), Village - Sund, Tehsil - Raisen, Dist. Raisen (MP)</u>

This is case of for Flag Stone. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 209), Village - Sund, Tehsil - Raisen, Dist.

Raisen (MP) 1.214 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज सेक की 607वीं बैठक दिनांक 21/11/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

12. <u>Case No 9410/2022 Shri Bhupendra Singh Sisodiya, Owner, Village - Ramnagar, Tehsil - Ichhawar, Dist. Sehore, MP - 466115, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (5001 Cum per annum) (Khasra No. 345), Village - Ramnagar, Tehsil - Ichhawar, Dist. Sehore (MP)</u>

This is case of for Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 345), Village - Ramnagar, Tehsil - Ichhawar, Dist. Sehore (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज सेक की 607वीं बैठक दिनांक 21/11/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

13. <u>Case No 8659/2021 Shri Vijay S/o Shri Kishor Kumar Jaiswal, 3, Bhoj Mohalla, Dist. Indore, MP Ammendment in Environment Clearance for Stone Quarry and M-Sand in an area of 4.0 ha. (Stone - 30000 cum per annum and M-Sand- 30,000 cum per annum) (Khasra No. 2480, 2526, 2527, 2541, 2542, 2543, 2552, 2553, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551), Village - Kampel, Tehsil - Khudel, Dist. Indore (MP)</u>

This is case of Stone Quarry and M-Sand Plant. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2480, 2526, 2527, 2541, 2542, 2543, 2552, 2553, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551), Village - Kampel, Tehsil - Khudel, Dist. Indore (MP) 4.0 Ha. The project requires ammenedment in EC.

परियोजना प्रस्तावक ने पर्यावरणीय अभिस्वीकृति में संशोधन बावत् फार्म–4 ऑन लाईन प्रस्तुत किया है जिसमें पूर्व में दिनांक 23/5/22 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति उत्पादन क्षमता स्टोन –60,000 मी.^{3}

607वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 नवम्बर 2022

प्रति वर्ष एवं मुरूम– 3648 मी^{3} प्रति वर्ष के स्थान पर संशोधित उत्पादन क्षमता स्टोन –30,000 मी.^{3} प्रति वर्ष, एम सेंड –30,000 मी.^{3} प्रति वर्ष हेतु अनुरोध किया है ।

प्रकरण सेक की 602वीं बैठक दिनांक 03/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री विजय जायसवाल (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए।

प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि ऑनलाईन प्रस्तुत शपथ–पत्र में परियोजना प्रस्तावक ने यह सूचित किया है कि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, इंदौरा द्वारा पत्र क्रमांक 1677 दिनांक 06/09/22 के माध्यम से खनिज गिट्टी पत्थर के साथ एम सेंड उत्खनन् हेतु अनुमति जारी की गई है तथा संशोधित खनन् योजना का अनुमोदन संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के पत्र क्रमांक पी–491/2022 दिनांक 25/8/22 के माध्यम से किया गया है। शपथ–पत्र में परियोजना प्रस्तावक ने उत्पादन क्षमता स्टोन –30,000 मी.^{3} प्रति वर्ष, एम सेंड –30,000 मी.^{3} प्रति वर्ष हेतु संशोधन तथा पर्यावरणीय स्वीकृति कि अवधि 08/9/22 से 07/9/32 तक करने का अनुरोध किया है ।

प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि आवेदक ने निर्धारित प्रपत्र फार्म–4 में कुछ जानकारियॉ अपूर्ण है जिसमें सुधार किया जाना आवश्यक है । समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार पुनरीक्षित फार्म–4 एवं जानकारियॉ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ताकि प्रकरण पर निर्णय लिया जा सके :–

1. फार्म–4 के सरल क्रमांक–8 पर Production Quantity as as per the approved EC Stone– 30,000 m3/year, M-Sand – 30,000 m3/year & Murrum - 3684 m3/year. दिया गया है जो जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार नहीं है, अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा फार्म–4 के सरल क्रमांक–8 उत्पादन क्षमता पत्थर–60,000 घनमीटर/वर्ष एवं मुरूम–3684 घनमीटर/ वर्ष हेतु पुनरीक्षित फार्म–4 प्रस्तुत करें ।
2. फार्म–4 के सरल क्रमांक–9 पर Details of Configuration में एम–सेंड/क्रेशर प्लांट का विवरण नही दिया गया है अतः इसको शामिल कर पुनरीक्षित फार्म–4 प्रस्तुत करें।
3. फार्म–4 के सरल क्रमांक–7 एवं 11 पर पर्यावरणीय स्वीकृति में आवश्यक संशोधन का विवरण स्पष्ट नहीं किया गया है, अतः परियोजना प्रस्तावक फार्म–4 के सरल क्रमांक–7 एवं 11 में आवश्यक संशोधन/क्षमता का उल्लेख करते हुए पुनरीक्षित फार्म–4 प्रस्तुत करें ।
4. फार्म–4 के सरल क्रमांक–12 पर Details of EIA Consultant में पर्यावरणीय सलाहकार को नही लिया जाना बाताया गया है किंतु फार्म–4 के सरल क्रमांक–13–ए के साथ संलग्न दस्तावेज/शपथ–पत्र में पर्यावरणीय सलाहकार मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बड़ौदरा, गुजरात का नाम दिया है अतः इसके संदर्भ में स्पष्टीकरण तथा पुनरीक्षित फार्म–4 प्रस्तुत करें ।
5. पूर्व की पर्यावरणीय अभिस्वीकृति दिनांक 23/5/22 को जारी हो गई थी । तत्पश्चात् पर्यावरणीय संरक्षण एवं सीईआर के तहत् किए गए कार्यो का व्यौरा दस्तावेजी प्रमाण के साथ प्रस्तुत करें ।
6. अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो।
7. पर्यावरणीय अभिस्वीकृति दिनांक 23/5/22 के संदर्भ में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त सी.टी.ई. की जानकारी प्रस्तुत करें, क्योंकि फार्म–4 के सरल क्रमांक–06–1 में सी.टी.ओ. की

जानकारी में ''नो'' लिखा है । यदि अभी तक सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त नहीं करने का कारण स्पष्ट करें ।

समिति द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 07/11/2022 को ए.डी.एस. जारी किया गया । उक्त ए.डी.एस. के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने दिनांक 08/09/202 को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है ।

प्रकरण को आज दिनांक 21/11/22 को समित के समक्ष विचारार्थ रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री विजय जायसवाल (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक ने फार्म–4 में संशोधित विवरण ऑनलाईन पी.डी.एफ. फार्मेट में प्रस्तुत कर दिया है । प्रस्तुतीकरण के परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा खनन् कार्य प्रारंभ नहीं किया है, इसलिए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सी.टी.ई./सी.टी.ओ.प्राप्त नहीं किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने यह भी उल्लेखित किया कि उनके द्वारा इस वर्षाकाल में आवंटित खनन् क्षेत्र की बाउण्ड्री एवं आसपास के क्षेत्र में 600–700 पौधें लगाये हैं । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत जानकारियॉ संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 30,000 मी^{3} प्रति वर्ष तथा एम–सेंड– 30,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 21.68 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 05.13 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू.02.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
ग्राम कम्पेल में:	
➢ गांव में मास्क (2000 nos) व सेनेटाइजर (200 nos) का ग्राम पंचायत के माध्यम से वितरण।	10,000/-
➢ ग्राम कम्पेल में शासकीय स्कूल में सोलर पैनल लगवाया जावेगा ।	20,000/-
➢ ग्राम कम्पेल में ओरल हाइजीन, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन व टीकाकरण एवं मवेशियों के स्वास्थ्य जांच आदि से संबंधित कार्य कराए जाएंगे (वर्ष में 1 बार)।	40,000/-
➢ "उज्वला योजना "के तहत ग्राम कम्पेल में सोलर कुकर/एलपीजी गैस सिलेंडर ग्राम पंचायत के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।	50,000/-
➢ ग्राम कम्पेल के आंगनवाड़ी केंद्र की पुताई एवं 5 दरियों का वितरण किया जावेगा।	10,000/-
➢ 2 स्ट्रेचर एवं 2 व्हील चेयर्स कम्पेल ग्राम के **प्राथमिक उपचार केंद्र** में उपलब्ध कराई जाएँगी।	30,000/-
➢ ग्राम कम्पेल में पंचायत के परमर्श से हैंडपंप लगवाया जावेगा।	80,000/-
सीईआर के तहत उल्लिखित गतिविधियों को संबंधित गांव में आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।	
योग	**2,40,000/-**

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय अभिस्वीकृति की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी ।

14. <u>Case No. - 5670/2018 Shri Maa Cimentech Pvt. Ltd, Shri Dileep Gupta, 158, 3rd Floor, Zone-II, M.P.Nagar, Bhopal MP – 462011 Prior Environment Clearance for Granite Deposit in an area of 11.0 Ha.. (33,501 ton per annum and M-Sand – 1,72,232 cum per annu) (Khasra no. Part 63) at Vill. Barha, Teh. Gaurihar, Dist. Chhatarpur, (MP)</u>

This is case of Granite Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal.The proposed site at (Khasra no. Part 63) at Vill. Barha, Teh. Gaurihar, Dist. Chhatarpur, (MP) 11.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

PP has submitted a copy of approved Mining Plan, information in the lease's within 500 meters radius around the site and other requisite information in the prescribed format duly verified in the Assistant Mining Officer, Distt. Chhatarpur vide letter no. 2918 dated: 04/12/2017 has reported that there is no more mine operating or proposed within 500 meters around the said mine.

The case was presented in SEAC 313th meeting on dated 18/04/18 by PP and their consultant wherein EIA/EMP and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC for Granite mining lease in an area of 11.00 ha., for 33,501 TPA at Khasra No. part 63 at Village –Barha Teh-Gaurihar, Distt-Chhatarpur- (M.P) subject to some conditions. प्रकरण में सिया के पत्र क्रमांक 908 दिनांक 31/5/18 के द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति ग्रेनाइट–33,501 टन/वर्ष के लिए जारी की गई थी ।

परियोजना प्रस्तावक ने फार्म–4 में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में ग्रेनाइट–33,501 टन/वर्ष के साथ–साथ एम–सेंड– 1,72,232 घनमीटर/वर्ष (को–प्रोडक्ट) हेतु संशोधन हेतु आवेदन किया गया है ।

प्रकरण सेक की 604वीं बैठक दिनांक 05/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिलीप कुमार गुप्ता (ऑनलाईन) एवं उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित गौर, मेसर्स काग्नीजेंस रिसर्च प्रा.लि, नोएडा उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया कि खदान में खनन् कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाले ओव्हर वर्डन से एम–सेंड बनाई जाना प्रस्तावित है तथा भविष्य में अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन् के दौरान उत्पन्न होने वाले 1,72,232 घनमीटर से ओव्हर वर्डन से एम–सेंड बनाई जायेगी । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वर्तमान में खनन् के दौरान अधिक मात्रा में वेदर्ड मटेरियल निकल रहा है, अतः यदि इसका उपयोग एम–सेंड बनाकर किया जाता है तो उसके लाभकारी उपयोग हो सकेगा तथा इस प्रकार वेस्ट मटेरियल का सदुपयोग हो सकेगा । परियेाजना प्रस्तावक ने बताया कि एम–सेंड प्लांट व्ही.एस.के. तकनीकी पर आधारित है, जिसमें वायु प्रदूषण की संभावना नगण्य है । इसी प्रकार एम–सेंड निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले दूषित जल का सेटलिंग के पश्चात् प्रक्रिया में पुनर्उपयोग किया जायेगा तथा उत्पन्न स्लज को स्लज ड्राइंग बेड में सुखाकर माइन पिट में अपवहित

किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस संशोधन हेतु उनके द्वारा खनन् अनुज्ञा पत्र (दिनांक 08/09/22) तथा संशोधित माइन प्लांन सक्षम अधिकारी से अनुमोदित (दिनांक 26/10/22) कराया गया है, जो ऑनलाईन अपलोड है । इसी प्रकार प्रस्ताव से संबंधित पुनरीक्षित पीएफआर एवं पुनरीक्षित पर्यावरण प्रबंधन योजना (एम–सेंड को शामिल करते हुए) तैयार की गई है, जो ऑनलाईन भी अपलोड है । समिति के पूछे जाने पर परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि फार्म–4 के सरल क्रमांक–11 पूर्ण विवरण ऑनलाईन फार्म भरते समय वर्ड की लिमिटेशन होने के कारण पूर्ण रूप से दर्शित नहीं हो रहे हैं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा नियमानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन सिया को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके विवरण उनकी वेबसाइट पर दर्शित है । समिति ने पाया कि सिया की वेबसाईट पर छःमाही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के विवरण निम्नानुसार दर्शित है :–

"Compliance report for the period of Jan. to June 19 received on 03-08- 19. Compliance report for the period of July to Dec. 19 received on 22-01-20. Compliance report for the period of Dec. 20 received on 18-12- 20. Compliance report for the period of June 21 received on 23-06-21. Compliance report for the period of June 22 received by email on dated 28-06-22".

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा विगत 02 वर्षो में 600 पौधें खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में, परिवहन मार्ग पर व ग्रामीण क्षेत्र में लगाये गये हैं, जिसके फोटोग्राफ प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न है । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में परियोजना प्रस्तावक को 1288 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था जिसके एवज् में परियोजना प्रस्तावक ने 02 वर्षो में 600 पौधें खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में, परिवहन मार्ग पर व ग्रामीण क्षेत्र में लगाये गये हैं, समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिया कि शेष 688 पौधे लगा कर उनके फोटोग्राफ एवं सी.इ.आर योजना के अतर्गत किये गये कार्यो का अनुपालन प्रतिवेदन सहित पुनः प्रस्तुत करे तत्पश्चात उनके प्रकरण पर पर्यावरण स्वीकृत के संशोधन संबंधी प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।

समिति द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 07/11/2022 को ए.डी.एस. जारी किया गया । उक्त ए.डी.एस. के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने दिनांक 09/09/202 को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है ।

प्रकरण को आज दिनांक 21/11/22 को समित के समक्ष विचारार्थ रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री दिलीप कुमार गुप्ता (ऑनलाईन) एवं उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित गौर, मेसर्स काग्नीजेंस रिसर्च प्रा.लि, नोएडा उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दिनांक 05/11/22 को समिति द्वारा द्वारा दिए गए निर्देशानुसार उनके द्वारा 700 पौधों का वृक्षारोपण (आवंटित खनन् क्षेत्र में 100 तथा ग्रामवासियों में वितरण 600) कराया गया है। इसी प्रकार सी.एस.आर. के तहत् रू. 2.65 लाख के कार्य कराये गये हैं, जिनका विवरण प्रस्तुतीकरण में दिया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत जानकारियॉ संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता ग्रेनाइट–33,501 टन/वर्ष एवं एम–सेंड– 1,72,232 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 48.42 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 16.12 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 04.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

B. FOR SOCIAL WELFARE- REVISED (CSR) (Please provide physical targets only) As per MoEF&CC OM dated 25/02/21		
S. No.	**Activity**	**Cost**
1.	Distribution of 10 LPG gas Cylinder (@5000/-) to mine workers.	**50,000/-**
2.	Solar energy System & LED Street light for primary school of Barha & Village Area @ 5,000 per Pole(@10polex5000) • 12 W Luminary Size is 35 x 15 x 15 cms. • Li-ion Battery (11.1 V) inbuilt into the luminary. • 20 W (2 pcs of 10 W) Solar panel size is 30 x 30 x 2 cms. • 3 mtr wire with Pin. • Lumens is 1000 Lm. Luminary is automatically turn on & off, Sensing darkness. • Opening on the luminary to accommodate bent pipe is 1”.	**50,000/-**
3.	2000 Fruit Bearing Plants (@50/-) (Aonla, Mango, Munga, Kathal, Imli, Guava, Papaya, Lemon, Harra, Bahera, Jamun) will be distribute in one year in village Barha. (This activity will be done under the **"Ankur Yojana"** of the Government of Madhya Pradesh.	**1,00,000 /-**
4.	In consultation with Gram Panchayat Barha 02 handpumps will be installed in village Barha.	**1,00,000/-**
5.	We will adopt Anganwadi of village Barha for one year and will bear its expenses.	**1,00,000/-**
	Total	**4,00,000/-**

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय अभिस्वीकृति की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी ।

15. <u>Case No 6819/2020 M/s Atul Polychem, 2nd Floor, Amit Apartment, E-5, Ratlam Kothi, Dist. Indore, MP – 452001 Prior Environment Clearance for Expansion in manufacturing of Synthetic Resin (From 2,700 to 11,000 MT/annum) at Khasra No. 58/1/K, Village - Raokhedi, Post - Mangaliya, AB Road, Tehsil - Sanwer, Dist. Indore (MP). Cat. - 5(f). Environmental Consultant:San Envirotech Pvt. Ltd. Ahmedabad.</u>

This is the case for Prior Environment Clearance for Expansion in manufacturing of Synthetic Resin at Khasra No. 58/1/k, Village - Raokhedi, Post - Mangaliya, AB Road, Tehsil - Sanwer, Dist. Indore (MP). The proposed project falls under item no 5(f).

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 425th SEAC meeting dated 26/02/20 wherein ToR was recommended.

607वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 नवम्बर 2022

EC recommended in 458 SEAC meeting dated 22-09-20. EC granted in 642 SEIAA meeting dated 05-10-20. EC issued vide letter no. 4519-20/SEIAA/20 dated 27-10-20.

SEIAA has sent the on-line case file to SEAC on 23-06-22 for EC amendment. PP has applied for EC amendment in the prescribed form- 4.

The case was presented by the PP and their consultant wherein PP submitted that as per granted EC the total water requirement of plant after expansion will increase to 10.5 KLD and waste water generation will be 6.5 KLD (Domestic 2.0 KLD, condensate from process 3.5 KLD & cooling bleed off 1.0 KLD). PP further submitted that in their submitted EIA report they have proposed to send industrial effluent to CETP after primary treatment at site. However, as per granted EC, it has been instructed by H'ble SEIAA/SEAC M.P. to ensure "Zero Effluent Discharge" from the unit by recycling. To ensure ZLD, industry had explored the possibility of installation of "Zero Liquid Discharge" Plant & reuses the treated water within the premises. However, the capital & maintenance cost for ZLD Plant is expensive. Investment on ZLD plant will be expensive for the industry and the industry would not be able to manufacture the final product at a reasonable cost due to which economic viability will be lost as the cost of ETP for this unit will be approx. 70.00 lakhs.Thus we request the H'ble SEIAA/SEAC M.P. for amendment in EC to allow us to send industrial effluent after primary treatment to CETP, Indore for further treatment & disposal. The case was scheduled for presentation and discussion in the 582nd SEAC meting dated 29/06/22 wherein after presentation PP was asked to submit following information for further consideration of the project:

1. Since during public hearing it was redommended by the district authorities that CETP at Sanwer Road, Indore is for the industries located in that area thus what are the zone of influence / consideration of CETP Sanwer Road, Indore? Please provide credible proof issued by the competent authorities to justify your proposal.
2. Detailed justification (component wise) of cost of proposed ETP for Rs. 75.00 lakhs.
3. How PP will ensure safe and spill proof transportation of waste water through tankers from plant site at Mangliya to CETP at Sanwer Road, Indore. How much distance will be travelled by road?

PP has submitted the online query reply raised in 582nd SEAC meeting dated 29.06.2022 through "Parivesh Portal" on dated 17.07.2022 and thus the cxase was scheduled in the 587th SEAC meeting dated 02/08/22. The case was presented by the PP Mr. Ajay Patel (online). During presentation it was observed by the committee that PP is unable to justify their request for amendment in previous EC conditions. PP is also unable to produce

credible proof of competent authorities prescribing the zone of influence / consideration of CETP Sanwer Road, Indore. Committee further observed that in the minutes of public hearing following recommendations were made by the competent authorities:

''उद्योग द्वारा दूषित जल का प्राथमिक उपचार कर इसे लगभग 18 किलोमीटर दूर सांवेर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित कॉमन इफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट में अंतिम रूप से उपचार एवं निष्पादन हेतु भेजे जाने का प्रस्ताव दिया गया है । यह मान्य योग्य नहीं है । उक्त सीईटीपी सांवेर रोड़ औद्योगिक हेतु स्थापित किया गया है, अतः उद्योग स्वयं के परिसर में विस्तृत दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना करेगा व उपचारित दूषित जल का पुनर्उपयोग उद्योग/परिसर में वृक्षारोपण हेतु किया जावेगा व उद्योग परिसर से बाहर शून्य निस्त्राव की स्थिति रखी जावेगी । उद्योग द्वारा घरेलू कार्यो से उत्पन्न दूषित जल को सोकपिट में छोड़े जाने का प्रस्ताव मान्य योग्य नहीं है । उद्योग द्वारा उपरोक्तानुसार परिसर में सीवेज सह इफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जावे व सभी प्रकार के दूषित जल का उपचार कर उसका पुनर्उपयोग सुनिश्चित् किया जावे'' ।

Considering above recommendations of public hearing a condition was imposed to install ETP and also to ensure "Zero Effluent Discharge". After deliberations, committee does not agree to the submissions made by PP as no logical answers/reasons are provided by PP to amend the conditions and decided to stands by its earlier recommendations made in 458th SEAC meeting dated 22/09/20.

सेक की उपरोक्त अनुशंसा पर प्रकरण को सिया की बैठक दिनांक 18/08/22 में रखा गया है। अध्यक्ष महोदय के समक्ष परियोजना प्रस्तावक उपस्थित होकर 03 निम्न दस्तावेज उपलब्ध कराये गये, जिन पर भी विचार किया गया :–

- इस संदर्भ में इण्डस्ट्रीज एसोसियशन के द्वारा Ministry of Chemical & Fertilizers Department of Chemicals & Pertro-chemicals Industry Facilitation Cell में पत्राचार किया गया था, जिसके जबाव में पत्र क्रमांक 28–58/1/2022–आईएफसी–सीपीसी दिनांक 29/07/22 के माध्यम से निम्न निर्देश प्राप्त हुए है :–
  "ZLD is not a compulsory condition. Project Proponent (PP) can apporoach EAC/MoEF&CC for seeking an amendment in EC (Envoironmental Clearance) if is not feasible for that PP"
- उपरोक्त पत्र के प्रकाश में यह भी विचार किया गया कि इकाई एक सूक्ष्म उद्योग श्रेणी की है, जिसके विस्तार की लागत 1.11 करोड़ की प्रस्तावित है । इकाई में ई.टी.पी. लगाना एक महंगा विकल्प होगा, जिससे ZLD की शर्त व्यवहारिक नहीं लगती हैं ।
- अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 1023 दिनांक 14/07/22 द्वारा नगर निगम, इंदौर को निर्देशित किया गया है कि मेसर्स अतुल पोलीकेम, राऊखेड़ी के फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित जल को प्राथमिक उपचार उपरांत नियमानुसर शुल्क के साथ उपचारित पानी को सी.ई.टी.पी.मे लेना सुनिश्चित् करें ।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरांत उपरोक्त उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों तथा तथ्यों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण को पुनः सेक को पुनः भेजा जाना चाहिए । साथ ही परियोजना प्रस्तावक उक्त दस्तावेज अनिवार्यतः ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से सेक को उपलब्ध करायें, जिससे सेक अपने निर्णय पर पुनः विचार कर सके ।

आज दिनांक 06/09/22 को उपरोक्त प्रकरण को समिति के समक्ष रखा गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि सिया के निर्देशानुसार परियोजना प्रस्तावक को निम्न दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु ए.डी.एस. जारी किया जाये :–

- Ministry of Chemical & Fertilizers Department of Chemicals & Pertro-chemicals Industry Facilitation Cell में पत्राचार किया गया था, जिसके जबाव में पत्र क्रमांक 28–58/1/2022–आईएफसी–सीपीसी दिनांक 29/07/22 के माध्यम से निम्न निर्देश प्राप्त हुए है :–
  "ZLD is not a compulsory condition. Project Proponent (PP) can apporoach EAC/MoEF&CC for seeking an amendment in EC (Envoironmental Clearance) if is not feasible for that PP" .
- अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 1023 दिनांक 14/07/22 द्वारा नगर निगम, इंदौर को निर्देशित किया गया है कि मेसर्स अतुल पोलीकेम, राऊखेड़ी के फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित जल को प्राथमिक उपचार उपरांत नियमानुसर शुल्क के साथ उपचारित पानी को सी.ई.टी.पी.मे लेना सुनिश्चित् करें ।

In this above context the case was scheduled for presentation in the 599th SEAC meeting dated 08.10.22 wherein It was observed that PP vide letter dated 17.09.2022 submitted on-line query reply which were asked in the SEAC 592nd meeting dated 06.09.22 . The case was presented by PP Shri G Ajay Patel, wherein PP submitted that they have uploadd the following documents:-

- Letter of Ministry of Chemical & Fertilizers Department of Chemicals & Petro-chemicals Industry Facilitation Cell is attached as Annexure-1 (vide dated 29.07.2022).
- Letter from ADM is attached as Annexure 2 (vide no. 1144 dated 18.08.22)
- Letter from CETP, Indore is attached as Annexure 3 (vide no. 1023 dated 14.08.22).

The committee obsedrved that Ministry of Chemical & Fertilizers Department of Chemicals & Petro-chemicals Industry Facilitation Cell is mentioned that ZLD is not a compulsory condition and PP can approach EAC, MoEF&CC for amendment in EC condition if it is not feasible for that PP.

607वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 नवम्बर 2022

- *कार्यालय कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 1144 दिनांक 18/08/22 के द्वारा यह लेख किया गया है, कि उनकी फैक्ट्री से निकलने वाले पानी को प्राथमिक उपचार उपरांत सी.ई.टी.पी. सांवेर भेजा जाता रहा है अतः प्राथमिक उपचार उपरांत नियमानुसार शुल्क के साथ मेसर्स अतुल पोलीकेम के उपचारित पानी को सी.ई. टी.पी. मे भेजना जारी रखने का अनुरोध किया गया है। मेसर्स अतुल पोलीकेम, राऊखेड़ी द्वारा कम्पनी से निकलने वाले पानी के लिये सी.ई.टी.पी. सांवेर को पानी के टैंकर का भुगतान देते रहे है ओर आगे भी देते रहेंगे।*

  कम्पनी द्वारा लोक सुनवाई के दौरान कहा गया था कि सांवेर इंडस्ट्रीयल एरिया में स्थित औद्योगिक इकाईयों को सांवेर सी.ई.टी.पी. में पानी भेजना आवश्यक है। ऐंसा कोई क्षेत्र/प्रभावित नियम नही है, कि सी.ई.टी.पी. सांवेर इंडस्ट्रीयल एरिया के बाहर औद्योगिक इकाईयों को सांवेर सी.ई.टी.पी. में पानी भेजना प्रतिबंधित है।

  अतः उपरोक्तानुसार अतुल पोलीकेम, राऊखेड़ी को सी.ई.टी.पी. सांवेर मे पानी भेजने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

- *अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 1023 दिनांक 14/07/22 द्वारा नगर निगम, इंदौर को निर्देशित किया गया है कि कि मेसर्स अतुल पोलीकेम, राऊखेड़ी के फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित जल को प्राथमिक उपचार उपरांत नियमानुसर शुल्क के साथ उपचारित पानी को सी.ई.टी.पी.मे लेना सुनिश्चित् करें ।*

The committee after deliberation obserbed that district authorities have recommended the proposal for CETP and PP has also addressed issues raised by committee except component wise of cost justification of proposed ETP of Rs. 75.00 lakhs. After deliberations committee recommends that issue of overseeing the recommendations of public hearing shall be decide by the SEIAA however, alternate methods/options proposed by PP seems to be reasonable considering economical viability for the project.

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 755वीं बैठक दिनांक 28/10/22 में प्रस्तुत हुआ है, जिसमें निम्न अतिरिक्त बिंदुओं पर जानकारी परियोजना प्रस्तावक से चाही गई है चूँकि जानकारी तकनीकी प्रकृति की है अतः उसके परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु प्रकरण सेक को भेजा गया है :–

1. What is the present arrangement of Industrial Waste Water Treatment?
2. There was a commitment of the representative of the industry of Primary and Secondary treatment within the Industrial complex. Accordingly detailed technical modified details of the proposed treatment plant with odour control measures should be given along with emergency storage arrangements of treated waste water.
3. It was decided in the last meeting that only the tertiary treatment of the wastewater will be done at CETP. In this regard detailed information is needed whether.
   a) CETP is designed and have required capacity remaining to treat the waste water for tertiary treatment. The process description in details should be given.

b) CETP is designed for ZLD and whether it is being practices.
c) For what quality parameters the CETP is designed and what is its present level of treatment quality wise.
d) The details about the foolproof procedure adopted for transportation of treated wastewater up to secondary level to the CETP by tanker or otherwise along with transportation routes should be given.
e) What are the emergency measures proposed for any mishap during transportation or when there is any temporary breakdown in the treatment plan both in industry and CETP.
f) Whether the CETP has valid EC of MPSEIAA and up to date consent of MPPCB
g) The detailed report along with supporting relevant documents, photographs etc should be given along with explanatory notes wherever required.

प्रकरण को आज दिनांक 21/11/22 को समित के समक्ष विचारार्थ रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अजय पटेल (ऑनलाईन) एवं उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मोलेक सुतार, मेसर्स सान इंवायरोटेक प्रा. लि., अहमदाबाद उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उपरोक्तानुसार चाहे गये सभी विवरण उनके द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोट एवं पूर्व में किये गये प्रस्तुतीकरण के दौरान दिये जा चुके है जिन पर विस्तृत चर्चा उपरांत समिति द्वारा प्रकरण संशोधन हेतु अनुशांसित किया गया था। सिया द्वारा उपरोक्तानुसार सी.ई.टी.पी. की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है जो प्रस्तुतीकरण में समाहित कर प्रस्तुत की जा रही है तथा उद्योग के प्राईमरी ट्रीटमेंट में सेंकड्री सिस्टम (बायोलोजिकल ट्रीटमेंट) प्रस्तावित किया गया है । उल्लेखनीय है कि सी.ई.टी.पी. इंदौर नगर निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है जिसकी अनापत्ती प्रमाण–पत्र पूर्व में ही सेक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा चुका है । समिति ने प्रस्तुतीकरण के उपरांत पाया कि उपरोक्तानुसार चाही गई अधिकांश जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिर्पोट एवं प्रस्तुतीकरण में दी जा चुकी है तथा सी.ई.टी.पी. में शोधन हेतु भी परियोजना प्रस्तावक द्वारा इंदौर नगर निगम की अनापत्ती प्रस्तुत की गई थी जिसके आधार पर ही सेक द्वारा अपनी अनुशांसा प्रेषित की गई थी । अतः समिति अपनी 599वी बैठक दिनांक 08/10/22 में की गई अनुशांसाओ को यथावत् रखती है।

16. <u>Case No 7817/2020 M/s Viscus Oils Pvt. Ltd, 55/1/2-C, New Palasia, Dist. Indore, MP – 452001 Prior Environment Clearance for Expansion in Manufacturing of Resin & other Edible/non-edible based products at Village - Raokhedi, Post - Mangaliya, A.B. Road, Tehsil - Sanwer, Dist. Indore (MP). Project Catogory- 5(f) Env. Con. M/s. SAN Envirotech Pvt. Ltd., Ahmedabad.</u>

This is case of Prior Environment Clearance for amendment in EC for manufacturing of Resin & other Edible/non-edible based products at Khasra no., Village - Raokhedi, Post - Mangaliya, A.B. Road, Tehsil - Sanwer, Dist. Indore (MP). Previously EC recommended in 545 SEAC meeting dated 29-01-22 and was granted in 706 SEIAA meeting dated 16-02-22. EC was issued vide letter dated 01-03-22.

PP applied for online for EC amendment through Parivesh Portal. In the SEAC 592nd Meeting dated 06-09-22 the case was presented by the PP Mr. Raj Patel, Director stating that the capital and maintenance cost for "ETP & RO Plant" is expensive for the plant. Investment on ETP & RO plant will be expensive for the industry and the industry would not be able to manufacture the final product at a reasonable cost due to which, economic viability is eventually lost. Thus we request for amendment in EC to allow us to send industrial effluent after primary treatment to CETP, Indore for further treatment & disposal. After presentation PP was asked to submit following information for further consideration of the project:

1. Since during public hearing it was redommended by the district authorities that PP shall install ETP and STP to maintain “Zero Liquid Discharge” and ensure its reuse. Since PP has now proposed to disposed its effluent after primary treatment in CETP, sanwer Road, Indore thus please provide credible proof issued by the competent authorities to justify your proposal i.e. openion of Collector and Regional Officer, MP Pollution Control Board, Indore.
2. What is the zone of influence / consideration of CETP Sanwer Road, Indore? Can CETP, Sanwer Road, Indore accepts effluent any where from the Indore city, please provide credible documents.
3. What are the conditions stipulated by MP Pollution Control Board in CTE/CTO issued after expansion for treatment & disposal of waste water?
4. Compliance of earlier EC conditions with verifiable documents from compitent authority.
5. Detailed justification (component wise) of cost of proposed ETP & RO.
6. How PP will ensure safe and spill proof transportation of waste water through tankers from plant site at Mangliya to CETP at Sanwer Road, Indore. How much distance will be travelled by road?

PP submitted that following documents are as:-

- The discharge of primary treated effluent from industry has been accepted by CETP, Indore (Indore Municipal Corporation, Indore) vide Letter No. 283 dated 23.06.2022. (Letter attached as Annexure1). The same has been authorized by Additional District Magistrate, Indore (Madhya Pradesh) vide Letter No. 1142/R.A.D.M/2022 dated 18.08.2022. (Letter attached as Annexure-2). The Additional District Magistrate is highest Authority in Public Hearing and conveyed to allow CETP discharge as per this aforesaid letter.

- Further, if we go through PH MOM, all present attendees accepted this project to be expanded and there were not even single suggestions / queries from public present over there. Even, we submitted in final EIA report CETP discharge after in-house primary treatment. Application to RO, MPPCB has also been submitted for there opinion. Acknowledgment letter is attached as Annexure 3. Further, in current CCA renewal Site visit report, the same CETP discharge and ETP operation found in smooth running operations. Further, there is Circular from Industrial Association from Ministry in consultation with MoEFCC saying that if PP is not feasible for implementation of "ZLD", SEAC/SEIAA/MoEFCC can't enforced to implement. Since industry is running 35 years in this region and ready to fulfill all the solicitation from SEAC/SEIAA and MPPCB.
- Regarding the zone of influence/ consideration of CETP Sanwer Road, Indore? Cen CETP, Sanwer Road, Indore accepts effluent any where from the Indore city, please provide credible documents. PP submitted that as per letter from ADM, Indore vide letter no. 1142/R.A.D.M/2022 dated 18.08.2022, there is no influence area defined of CETP to accept water from industry stating there is no influence / zone of consideration of the same. Also, ADM, Indore has directed to CETP to accept wastewater of Viscus after primary treatment. Letter is already attached as Annex- 2.
- What are the conditions stipulated by MP Pollution Control Board in CTE/CTO issued after expansion for treatment & disposal of waste water? PP submitted that Due to Covid Pandemic and non-feasibility of ZLD, construction has not been started at the site for expansion work. Therefore, CTE/CTO for expansion shall be taken after grant of Amendment in EC.
- Compliance of earlier EC conditions with verifiable documents from competent authority- As per the MoEF&CC guideline, Environment monitoring report and compliance of conditions mentioned in the environmental clearance needs to be submitted in month of June and December for the period of October to March and April to September respectively. As first environmental clearance has been granted to plant on 01.03.2022, thus first compliance report of EC is due in December, 2022 for the period of April to September. Also, no work w.r.t to expansion of project is started at site.
- Detailed justification (component wise) of cost of proposed ETP &RO. - Component of Proposed ETP along with Evaporator is attached as Annexure 4.

- How PP will ensure safe and spill proof transportation of wastewater through tankers from plant site at Mangaliya to CETP at Sanwer Road, Indore. How much distance will be travelled by road?- To ensure safe and spill proof transportation of wastewater from plant site to CETP, Sanwer Road, the following measures will be implemented:

1. There will be dedicated tankers duly labelled in accordance with the Motor Vehicles Act (with regard to transportation of hazardous waste), to collect pre-treated effluent and for transportation to CETP following the manifest system.
2. GPS tracking system shall be provided in tankers.
3. Regular maintenance and inspection of equipment.
4. Machinery subjected to high use shall have annual replacement of hoses, fittings, seals, and hydraulic lines.
5. Machinery subjected to low annual use shall have components changed every 3 years.
6. Pay particular attention to proper installation of seals, fittings, etc.
7. Consult an equipment/parts supplier to determine the appropriate maintenance schedule for equipment use.
8. Inspection of all fuel, oil, or fluidcontaining fittings, hoses, and seals during machinery operation to detect leaks shall be done on regular routine.
9. Use of double-walled hydraulic fluid tanks will lessen the likelihood of leaks due to tank rupture.
10.. Clean-up materials shall be readily available at all times.
11.. Spill kit containers will be rigid plastic barrels or buckets or soft duffel bags. The container serves both for storage of clean materials and for disposal of soiled materials.

In this above context the case was scheduled for presentation in the 599th SEAC meeting dated 08.010.22 wherein It was observed that PP vide letter dated 17.09.2022 submitted on- line query reply which were asked in the SEAC 592nd meeting dated 06.09.22 . The case was presented by Shri Shri Maulik Sutar ,Env. Consultant from M/s. San Envirotech Pvt. Ltd and Shri Raj Patel Patel on behalf of PP,

The committee after deliberation obserbed that district authorities have recommended the proposal for CETP and PP has also addressed issues raised by committee except component

wise of cost justification of proposed ETP of Rs. 75.00 lakhs. After deliberations committee recommends that issue of overseeing the recommendations of public hearing shall be decide by the SEIAA however, alternate methods/options proposed by PP seems to be reasonable considering economical viability for the project.

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 755वीं बैठक दिनांक 28/10/22 में प्रस्तुत हुआ है, जिसमें निम्न अतिरिक्त बिंदुओं पर जानकारी परियोजना प्रस्तावक से चाही गई है चूँकि जानकारी तकनीकी प्रकृति की है अतः उसके परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु प्रकरण सेक को भेजा गया है :–

1. What is the present arrangement of Industrial Waste Water Treatment?
2. There was a commitment of the representative of the industry of Primary and Secondary treatment within the Industrial complex. Accordingly detailed technical modified details of the proposed treatment plant with odour control measures should be given along with emergency storage arrangements of treated waste water.
3. It was decided in the last meeting that only the tertiary treatment of the wastewater will be done at CETP. In this regard detailed information is needed whether.
   - h) CETP is designed and have required capacity remaining to treat the waste water for tertiary treatment. The process description in details should be given.
   - i) CETP is designed for ZLD and whether it is being practices.
   - j) For what quality parameters the CETP is designed and what is its present level of treatment quality wise.
   - k) The details about the foolproof procedure adopted for transportation of treated wastewater up to secondary level to the CETP by tanker or otherwise along with transportation routes should be given.
   - l) What are the emergency measures proposed for any mishap during transportation or when there is any temporary breakdown in the treatment plan both in industry and CETP.
   - m) Whether the CETP has valid EC of MPSEIAA and up to date consent of MPPCB
   - n) The detailed report along with supporting relevant documents, photographs etc should be given along with explanatory notes wherever required.

प्रकरण को आज दिनांक 21/11/22 को समित के समक्ष विचारार्थ रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राज पटेल (ऑनलाईन) एवं उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मोलेक सुतार, मेसर्स सान इंवायरोटेक प्रा. लि., अहमदाबाद उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उपरोक्तानुसार चाहे गये सभी विवरण उनके द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोट एवं पूर्व में किये गये प्रस्तुतीकरण के दौरान दिये जा चुके है जिन पर विस्तृत चर्चा उपरांत समिति द्वारा प्रकरण संशोधन हेतु अनुशांसित किया गया था। सिया द्वारा उपरोक्तानुसार सी.ई.टी.पी. की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है जो प्रस्तुतीकरण में समाहित कर प्रस्तुत की जा रही है तथा उद्योग के प्राईमरी ट्रीटमेंट में सेंकड्री सिस्टम (बायोलोजिकल ट्रीटमेंट) प्रस्तावित किया गया है । उल्लेखनीय है कि सी.ई.टी.पी. इंदौर नगर निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है जिसकी अनापत्ती प्रमाण–पत्र पूर्व में ही सेक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा

चुका है । समिति ने प्रस्तुतीकरण के उपरांत पाया कि उपरोक्तानुसार चाही गई अधिकांश जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिर्पोट एवं प्रस्तुतीकरण में दी जा चुकी है तथा सी.ई.टी.पी. में शोधन हेतु भी परियोजना प्रस्तावक द्वारा इंदौर नगर निगम की अनापत्ती प्रस्तुत की गई थी जिसके आधार पर ही सेक द्वारा अपनी अनुशांसा प्रेषित की गई थी । अतः समिति अपनी 599वी बैठक दिनांक 08/10/22 में की गई अनुशांसाओ को यथावत् रखती है।

17. मान्नीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा आई.ए. क्रमांक 1000/2003 एवं डब्ल्यू.पी.(सिविल) 202/1995 में पारित आदेश दिनांक 03 जून, 2022 पर चर्चा

मान्नीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा आई.ए. क्रमांक 1000/2003 एवं डब्ल्यू.पी.(सिविल) 202/1995 में पारित आदेश दिनांक 03 जून, 2022 पर आज समिति के बैठक के दौरान चर्चा की गई । इस आदेश के पृष्ठ–53 एवं 54 पर बिंदु क्रमांक–44 (ए) एवं (बी) में निम्न निर्देश दिए गए हैं :–

44– (a)

Each protected forest that is national park or wildlife sanctuary must have an ESZ of minimum one kilometre measured from the demarcated boundary of such protected forest in which the activities proscribed and prescribed in the Guidelines of 9th February 2011 shall be strictly adhered to. For Jamua Ramgarh wildlife sanctuary, it shall be 500 metres so far as subsisting activities are concerned".

44– (b)

In the event, however, the ESZ is already prescribed asper law that goes beyond one kilometre buffer zone, the wider margin as ESZ shall prevail. If such wider buffer zone beyond one kilometre is proposed under any statutory instrument for a particular national park orwildlife sanctuary awaiting final decision in that regard, then till such final decision is taken, the ESZ covering the area beyond one kilometre as proposed shall be maintained.

मान्नीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय आज की बैठक में सरल क्रमांक 01 पर उल्लेखित प्रकरण Case No 9082/2022 Shri Jagdish S/o Shri Ramchandra, Village - Jabardi, Tehsil - Pachore, Dist. Rajgarh, MP के प्रस्तुतीकरण के दौरान चर्चा मे आया कि वन मण्डलाधिकारी, कार्यालय वन मण्डल, सामान्य, राजगढ़ (व्यावरा) म.प्र. ने पत्र क्रमांक 2758 दिनांक 06/11/22 के माध्यम से सूचित किया है कि मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट पिटिशन (एस) (सिविल) 202/1995 में पारित आदेश दिनांक 03/06/2022 के बिंदु क्रमांक–44(बी) अनुसार सर्वे क्रमांक 507/2 रकबा 18.564 हे. में से अंश रकबा 01.00 हे. पर नवीन मुरम उत्खनन् पट्टा जामोन्या जोहर तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ वन्यप्राणी अभ्यारण्य नरसिंहगढ़ की अधिसूचित परिस्थितिकीय संवेदी जोन (ईको सेंसेटिव जोन) की सीमा 02 किलोमीटर के अंदर 1630 मीटर पर स्थित है । मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के आधार पर अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में कोई स्वीकृति जारी नहीं की जायें । समिति ने पाया कि उपरोक्तानुसार आदेश 44 (ए) एवं (बी) अनुसार अधिसूचित परिस्थितिकीय संवेदी जोन (ईको सेंसेटिव जोन) की सीमा न्यूनतम् 01 किलोमीटर कर दी गई है । कई नेशनल पार्क / अभ्यारण्य जहॉ पर पूर्व में अधिसूचित परिस्थितिकीय संवेदी जोन (ईको सेंसेटिव जोन) की सीमा 01 किलोमीटर से कम है (जैसेः वन विहार नेशनल पार्क–100 मीटर, घुघवा फासिल नेशनल पार्क–250 मीटर, केन घड़ियाल अभ्यारण्य–200 मीटर इत्यादि) वहॉ पर सीमा उपरोक्त आदेश के

अनुसार 01 किलोमीटर मानी जाये अथवा पूर्व में किए गए नोटिफिकेशन अनुसार । इस संदर्भ में समिति की अनुशंसा है कि सिया द्वारा इस संबंध में विधिक मत प्राप्त किया जाये ताकि आगामी प्रकरणों में निर्णय लेने में सुविधा हो सके।

17 जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो पर चर्चा –

निम्नानुसार उल्लेखित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट आज की बैठक के दौरान प्रस्तुत की गयी। यह प्रकरण एजेण्डा में सूचीबद्ध नहीं था किंतु मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा चर्चा की अनुमति प्रदान की गई।

अ. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, श्योपुर (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)

Mineral	**Other than Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 601st Meeting dated 19.10.2022
Deliberation in the SEAC 601st Meeting dated 19.10.2022	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 610वीं बैठक दिनांक 19/10/22 जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला श्योपुर (म. प्र.)** कार्यालय कलेक्टर के पत्र क0. 11099 दिनांक 12/10/22 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट– श्योपुर (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिति का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है। जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पायाः– • जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चैप्टर –09 (पेज न0. 15–22) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे गई है। • जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी मे नही दी गई है • जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न0. 31–32 में जो मेटर दिया गया है वह स्पष्ट पढ़ने में नही आ रहा है। इन पेजों में Text आपस में मिल रहा है । चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि श्योपुर की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज एंव रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत की जावे।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	श्योपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट ई–मेल के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिसमें कव्हरिंग लेटर व हार्ड कापी प्रस्तुत नहीं की गई हैं ।

आज दिनांक 21/11/22 को श्योपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी उपस्थित नहीं हुए।

समिति ने पाया कि श्योपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट ई–मेल के माध्यम से प्राप्त हुई है,

जिसमें कव्हरिंग लेटर व हार्ड कापी प्रस्तुत नहीं की गई हैं और न ही कोई सक्षम अधिकारी प्रस्तुत हुए । समिति ने प्राप्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं पाया कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी नहीं दी गई है, जो निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप नहीं है । अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि संबंधित खनिज अधिकारी उपरोक्त जानकारी का समावेश कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पुनः अनुमोदन हेतु कव्हरिंग लेटर व हार्ड के साथ प्रस्तुत करें ।

ब. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, गुना (अन्य गौण खनिज – गिट्टी एंव मुरूम)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना म.प्र. ने पत्र 1200 दिनांक 16/11/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि गुना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट **(अन्य गौण खनिज –गिट्टी एंव मुरूम) की तैयार की है। प्रभारी खनिज अधिकारी ने** संदर्भित पत्र में प्रस्तुत किया कि जिला सर्वेक्षण रिर्पोट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले पोर्टल पर 30 दिवस की समयावधि हेतु अपलोड किया गया था तथा 21 दिन के भीतर कोई सुझाव/आपत्ति प्राप्त नहीं हुए है। इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक 26/07/2022 को किया गया।

आज दिनांक 21/11/22 को गुना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी उपस्थित नहीं हुए।

Mineral	**Other Minor Minerals (Stone & Murrum)**
Earlier DSR Discussed	New DSR
Revised District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Guna No. 1200 dated 16.11.2022
SEAC meeting dated 21/11/22	**अन्य गौण खनिज –गिट्टी** ● जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चैप्टर –08 (पेज न0. 24–40) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे गई है। ● जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी चैप्टर –08 (पेज न0. 24–40) मे दी गई है **अन्य गौण खनिज –मुरूम** ● जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चैप्टर –08 (पेज न0. 24–27) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे गई है। ● जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी चैप्टर –08 (पेज न0. 24–27) मे दी गई है

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला–गुना के पत्र क्र0 1200 दिनांक 16/11/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, पौधों की संख्या एंव प्रजाति भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति की अनुशंसा है कि गुना जिले की दोनों जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज –गिट्टी एंव मुरूम) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

607वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 नवम्बर 2022

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'
Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    f. Lease owner's Name, Contact details etc.

g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
i. Minable Potential of sand mine.
j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
k. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
    vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'C'
Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain

a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    l. Lease owner's Name, Contact details etc.
    m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    o. Minable Potential of sand mine.
    p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    q. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।

- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
    - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

35. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained